



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 11, 1969 (पौष 21, 1890)

No. 2]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 11, 1969 (PAUSA 21, 1890)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 7 दिसम्बर 1968 तक प्रकाशित किए गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 7th December 1968 :—

अंक	संख्या और तारीख	द्वारा जारी किया गया	विषय
Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
1	2	3	4

229. No. 1(1)/-Tar/68, dated 7th December, 1968. Min. of Commerce

Report of the Tariff Commission under sections 11(e) and 13 of the Tariff Commission Act, 1951.

संख्या १(१)-टैरिफ/६८, दिनांक ७-१२-६८

वाणिज्य मंत्रालय

टैरिफ आयोग द्वारा, टैरिफ आयोग अधिनियम १९५१ की धाराओं ११(क) तथा १३ के अन्तर्गत उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these *Gazettes*.

विषय-सूची (CONTENTS)

भाग I—खंड 1.—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	पृष्ठ 39	भाग II—खंड 3.—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं ..	पृष्ठ 69
भाग I—खंड 2.—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	39	भाग II—खंड 4.—रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश ..	9
भाग I—खंड 3.—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	—	भाग III—खंड 1.—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..	29
भाग I—खंड 4.—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	23	भाग III—खंड 2.—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	11
भाग II—खंड 1.—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..	—	भाग III—खंड 3.—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	3
भाग II—खंड 2.—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट ..	—	भाग III—खंड 4.—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	15
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ..	57	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	5
		पूरक संख्या 2—	
		4 जनवरी 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट ..	43
		14 दिसम्बर 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बिमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े ..	57
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	Page 39	PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	Page 69
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	39	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	9
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence ..	—	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	29
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence ..	23	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	11
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations ..	—	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	3
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills ..	—	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	15
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	57	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	5
		SUPPLEMENT No. 2—	
		Weekly Epidemiological Reports for week-ending 4th January 1969 ..	43
		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 14 December 1968 ..	57

भाग I—खंड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 1968

सं० 5(3)/67-एस० आर०-I—राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की संस्था के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 89 (iii) के उपबन्धों के अन्तर्गत, राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को निगम निदेशक बोर्ड के निदेशकों के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

1. डा० बी० डी० कालेसकर के स्थान पर डा० ए० सीतारमैया, वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार (रसायन), तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली।

2. श्री पी० एन० माथुर के स्थान पर श्री एम० श्री निवासन, महानिदेशक, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन, लखनऊ।

बी० एन० भारद्वाज उप-सचिव

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 1968

विषय :—राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यपुस्तक बोर्ड की स्थापना

सं० एफ० 18-22/68-बी० एस० ई० 2—श्रीमगर में जून, 1968 में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों की समस्या पर विचार किया गया था। परिषद् ने राष्ट्रीय एकता के प्रयोजनों के लिये पाठ्यपुस्तकों के उचित प्रयोग को बहुत महत्व दिया। उसका विचार था कि प्राथमिक स्तर से लेकर उत्तर-स्नातक तक की शिक्षा का पुनर्नूस्थापन किया जाए ताकि वह—(क) भारतीयता, एकता और दृढ़ता की भावना पैदा करने का उद्देश्य पूरा करने; (ख) भारतीय प्रजातन्त्र के बुनियादी तत्वों में विश्वास कायम करने; और (ग) एक आधुनिक समाज के निर्माण में राष्ट्र की सहायता करने में सफल हो सके। परिषद् की यह भी सिफारिश थी कि स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में सुधार के लिये आमतौर पर तथा विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता के लिये उनका प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने के लिये राज्य स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा एक उपयुक्त संगठन का निर्माण किया जाए तथा भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यपुस्तक बोर्ड स्थापित किया जाए जो राज्य सरकारों के प्रयत्नों में समन्वय स्थापित करे।

2. स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों की कोटि सुधारने के कार्यक्रमों को माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) की सिफारिशों के आधार पर प्रारम्भ किया गया था। मोटे तौर पर उनके दो रूप हैं :—

(1) राज्य सरकारों ने पाठ्यपुस्तकों के राज्य स्तर पर निर्माण के लिये संगठन स्थापित किए हैं और निजी क्षेत्र में तैयार की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों के अनुमोदन सम्बन्धी मशीनरी का सुधार किया है; और

(2) भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अधीन स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों को सुधारने के लिये राज्य सरकारों की सहायता एक कार्यक्रम विकसित करने का प्रयत्न किया है।

3. स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों के सुधार के लिये राष्ट्रीय और राज्यीय कार्यक्रमों के फलस्वरूप अभी तक प्राप्त अनुभव, इस सम्बन्ध में शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए सुझाव, और राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के बाद भारत सरकार का विचार, राज्य सरकारों के सहयोग से, स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों को सुधारने तथा राष्ट्रीय एकता के प्रयोजनों के लिये उनके प्रभावशाली प्रयोग के लिये एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने का है।

4. राज्य स्तर पर स्कूली पाठ्यपुस्तकों के निर्माण और निर्धारणसंबन्धी संगठन में सुधार—राज्यों में स्कूली पाठ्यपुस्तकों के निर्माण और अनुमोदन की विद्यमान व्यवस्था में, शिक्षा आयोग द्वारा मोटे तौर पर की गई सिफारिशों के अनुसार सुधार किया जाना चाहिये विशेष रूप से, स्कूली पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिये विशेषज्ञ समितियां नियुक्त करने के लिये राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिये; और सांघ-जनिक क्षेत्र में स्कूली पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिये राज्य स्तर पर स्वायत्त पुस्तक निगम स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जाना चाहिये।

5. राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना और राज्य स्तर कार्यक्रमों के साथ उसका परस्पर संबंध—राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के कार्यक्रमों का विस्तार किया जायगा और उसमें नीचे लिखे अनुसार सुधार किया जायगा :—

(1) पाठ्यपुस्तक सामग्री के निर्माण पर बल दिया जायगा।

- (2) पाठ्यपुस्तकों के निर्माण और अनुमोदन के लिये क्रियाविधि और पाठ्यचर्याएं सुधारने की इच्छुक राज्य सरकारों को शैक्षिक सहायता प्रदान की जाएगी ।
- (3) राज्य सरकारों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर, पाठ्यपुस्तकों की शैक्षणिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोणों से संवीक्षा की जाएगी और सम्बन्धित राज्य सरकारों को उपयुक्त सलाह उपलब्ध की जाएगी :
- (4) देश में प्रयोग की जाने वाली सभी स्कूली पाठ्यपुस्तकों का एक केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा; और चुनी हुई पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करने और ऐसे मूल्यांकनों की रिपोर्ट सम्बन्धित राज्य सरकारों को उपलब्ध कराने का एक नियमित कार्यक्रम होगा ।
- (5) एक कार्यक्रम के अन्तर्गत, देश के विभिन्न भागों में नमूने के रूप में प्रयोग की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से निरन्तर सर्वेक्षण किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिये उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने सम्बन्धी सुझाव राज्य सरकारों और भारत सरकार के पास भेजे जाएंगे ।
- (6) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, दोनों में, राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में लगे व्यावसायिक व्यक्तियों के बीच कार्य सम्बन्धी घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित किया जाएगा ।
- (7) राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में एक सलाहकार समिति होगी जिस में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में पाठ्यपुस्तकों के निर्माण सम्बन्धी संगठनों के प्रतिनिधि और अध्यापक तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे ।

6. पाठ्यपुस्तकों के निर्माण और सुधार के लिये राष्ट्रीय और राज्यीय संगठनों को मार्गदर्शन प्रदान करने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने के लिये, राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार इस संकल्प के अनुसार इसी समय से एक राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यपुस्तक बोर्ड की स्थापना करती है ।

7. कार्य : बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

- (1) स्कूल पाठ्यपुस्तकों के निर्माण और निर्धारण से सम्बन्धित सभी मामलों पर, भारत सरकार और राज्य सरकारों की सलाह देना ;
- (2) राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर निर्माण की गई पाठ्यपुस्तकों की जांच पड़ताल करना और इस बात को देखना कि वे राष्ट्रीय एकता के उद्देश्यों के अनुरूप ह ।
- (3) यह सुनिश्चित करना कि पाठ्यपुस्तकों की सामग्री और विषय वस्तु को सुधारने, सामग्री के प्रस्तुतीकरण और निर्माण में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर लगातार प्रयत्न किये जाते हैं और इस प्रयोजन के के लिये, पाठ्यपुस्तकों विशेषकर इतिहास, भाषा और

समाज अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिये कोई उपयुक्त मापदण्ड तैयार करना ; और

- (4) यह सुनिश्चित करना कि आवश्यक मापदण्डों को बनाए रखते हुए पाठ्यपुस्तकों का मूल्य यथा सम्भव कम रखा जाता है और ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी सभी पाठ्यपुस्तकें आसानी से मिल सकें ।

8. गठन : बोर्ड का गठन इस प्रकार होगा :—

- (क) केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री—अध्यक्ष
- (ख) सभी राज्यों और ऐसे सभी संघीय क्षेत्रों के शिक्षा मन्त्री, जिन में विधान सभाएं हैं तथा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पर्वद ।
- (ग) शिक्षाविद तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण क्षेत्र के विभिन्न हितों तथा सम्बन्धित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञ—सोलह
- (घ) शिक्षा मन्त्रालय का एक अधिकारी—सदस्य सचिव

राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यपुस्तक बोर्ड में, अध्यापकों तथा शिक्षा से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों का पर्याप्त, प्रतिनिधित्व रहेगा ।

9. बोर्ड एक स्थायी समिति के माध्यम से अपना कार्य करेगा और इस समिति की सहायता विभिन्न विषयों में विशेषज्ञों के पैनल करेंगे ।

10. राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, पाठ्यपुस्तकों की जांच पड़ताल, अनुमोदन और निर्माण में लगी, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की संस्थाओं की सहायता करने और उनके विचार-विनिमय के लिये समस्याओं को पेश करने तथा उसके फलस्वरूप लिये गये निर्णयों पर अमल करने के लिये, बोर्ड को आवश्यक सभी शिक्षा सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था करेगी ।

11. बोर्ड की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी, किन्तु जितनी बार आवश्यक हो, उतनी बार बुलाई जा सकती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों तथा सभी संघीय क्षेत्रों के प्रशासकों तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सर्वसाधारण की सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

जी० के० चंदीरामाणी, सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 24 दिसम्बर 1968

सं० 24/3/68-एफ० पी०—समय समय पर संशोधित, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या 1/29/58 एफ० पी० तारीख 5 फरवरी, 1959 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने श्री आर० पी० नायक के स्थान पर केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष श्री एम० बी० देसाई को उनके अपने कार्य के साथ साथ इस अधिसूचना की तिथि से अगले आदेश तक, फिल्म सलाहकार, बोर्ड, बम्बई का अध्यक्ष नामांकित किया है ।

वानूराम अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING & URBAN DEVELOPMENT

(Department of Family Planning)

RESOLUTION

New Delhi, the 31st December 1968

No. 25-8/68-ME&M(FP).—The Government of India are pleased to reconstitute the Films Committee which was constituted in the Ministry of Health, and Family Planning Resolution No. 17-4/66-ME&M(FP), dated the 28th February, 1967.

2. The composition of the reconstituted Committee will be as under :—

Chairman

1. Chief Producer (Films), Ministry of Information and Broadcasting.

Members

2. Deputy Commissioner (FP), (Training).
3. Director, Directorate of Field Publicity Organisation.
4. Director, Indian Institute of Mass Communication.
5. Deputy Financial Adviser, Ministry of Health, Family Planning & Urban Development.

Member-Secretary

6. Assistant Commissioner (Media), Department of Family Planning.

The Committee shall have the power to invite other experts to attend its meeting.

3. The terms of reference of the Committee will be to advise on ways and means of organising an effective programme of preparation and use of films for propagating the Family Planning Programme and advise on films which should be produced/procured and the basis on which these films should be procured for use in the national Family Planning Programme. The recommendations should be based on detailed technical factors which should be expressly stated while making recommendations to the Government.

4. The life of the Committee shall be one year and the Committee shall normally meet at Delhi once in two months.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. N. SRIVASTAVA, Jt. Secy. (F.P.)

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 26th December 1968

No. 1-15/68-GOP(Supp. List 17).—In continuation of this Department Notification No. 1-5/66-GOP (Suppl. List 16) dated 15-6-68, the following Wholesale Consumer Cooperative Society is added to the Schedule of Cooperative Societies published alongwith the Notification No. 1-25/65-CC dated 27-5-66 containing the Guarantee Scheme for Wholesale Consumer Cooperatives :

Adilabad Consumers Cooperative Central Stores Ltd, Adilabad (Andhra Pradesh).

V. V. NATHEN, Dy. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 27th December 1968

No. 5(3)/67-SR.I.—Under the provisions of Article 89(iii) of the Articles of Association of the National Research Development Corporation of India, the President is pleased to appoint the following as Directors of the Board of Directors of the Corporation :—

1. Dr. A. Seetharamiah, Senior Industrial Adviser (Chemicals) Directorate General of Technical Development, New Delhi, vice Dr. B. D. Kalelkar.

2. Shri M. Srinivasan, Director General, Research Designs and Standards Organisation, Lucknow vice Shri P. N. Mathur.

B. N. BHARDWAJ, Dy. Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 31st December 1968

SUBJECT—Establishment of a National Board of school Text-Books.

No. F. 18-22/68-BSE.2(BSE.1).—The problem of school text-books was discussed at the meeting of the National Integration Council held at Srinagar in June 1968. The Council attached great significance to the proper use of text-books for purposes of national integration. It was of the view that education from primary to the post-graduate stage should be reoriented (a) to serve the purpose of creating a sense of indianness, unity and solidarity; (b) to inculcate faith in the basic postulates of Indian democracy; and (c) to help the nation to create a modern society. It also recommended that the State Governments should create an appropriate machinery at the State level for improvement of school text-books in general and for using them effectively for purposes of national integration in particular and that a National Board of School Textbooks which will coordinate the efforts of the State Governments should be set up by the Government of India.

2. Programmes of improving the quality of school text-books were initiated on the recommendations of the Secondary Education Commission (1952). These have broadly assumed two directions :—

- (1) The State Governments have set up organisations for State production of textbooks and have reformed the machinery for approving textbooks produced in the private sector; and
- (2) The Government of India has tried to develop, under the National Council of Educational Research and Training (NCERT) a programme of help to the State Governments to improve school textbooks.

3. After taking into consideration the experience so far gained in the national and State programmes for the improvement of school textbooks, the proposals made by the Education Commission in this behalf, and the recommendations of the National Integration Council, the Government of India proposes to develop, in collaboration with the State Governments, an intensive programme for the improvement of school textbooks and for their effective utilisation for the purposes of national integration.

4. Improvement of the Machinery for production and Prescription of School Textbooks at the State level : The existing arrangements in the States for production and approval of school textbooks should be improved, on the broad lines recommended by the Education Commission. In particular, the State Governments should take steps to appoint committees of experts for preparation of school textbooks; and the possibility of establishing autonomous book corporations at the State level for the production of school textbooks in the public sector should be examined.

5. Strengthening of the National Programme and its Correlation with the State Level Programmes : The programmes of producing textbooks at the national level will be expanded and improved on the following lines :—

- (1) Emphasis will be placed on the production of textbook materials;
- (2) Academic assistance will be offered to State Governments desiring to improve curricula and procedures for production and approval of textbooks;
- (3) On requests made by the State Governments, textbooks will be scrutinised from academic and national points of view and suitable advice should be made available to the State Governments concerned;
- (4) A Central Library of all school textbooks used in the country will be built up; and there will be a regular programme of evaluating selected textbooks and making the reports of such reviews available to the State Governments concerned;

- (5) There will be a programme under which a random sample of textbooks used in different parts of the country will be continuously examined from the point of view of national integration and suggestions to make them more effective for this purpose will be brought to the notice of the State Governments and the Government of India;
- (6) Close working relationships will be established between professional persons engaged in textbooks production at the national and State levels, both in the public and private sectors; and
- (7) There will be an Advisory Committee in the National Council of Educational Research and Training comprising representatives of organisations for textbooks production in the public and private sector and teachers and experts in the field.

6. In order to coordinate and guide the activities of national and State Organisations for production and improvement of textbooks, the Government of India hereby establishes a National Board of School Textbooks as recommended by the National Integration Council with immediate effect.

7. *Functions* : The functions of the Board will be.

- (1) to advise the Government of India and State Governments on all matters relating to the production and prescription of school textbooks;
- (2) to scrutinise textbooks produced at the State and the national levels and to ensure that they are in conformity with the objectives of national integration;
- (3) to ensure that continuous efforts are made at the national and State levels to improve the standard of textbooks in subject-matter content, in presentation of material and in production; and to this end, to evolve appropriate criteria for the production of textbooks, especially for those in history, languages and social studies; and
- (4) to ensure the textbooks are priced as low as possible consistently with the maintenance of essential standards and that all necessary steps are taken to give every pupil a reasonable access to all his textbooks.

8. *Composition* : The composition of the Board will be as follows :—

- (a) Union Minister of Education—*Chairman*.

- (b) All Education Ministers of States and Union Territories having legislatures and the Chief Executive Councillor of Delhi.
- (c) Sixteen educationists and experts in the field of textbooks production representing various allied interests and expertise.
- (d) An officer of the Ministry of Education—*Member-Secretary*.

The National Board of School Textbooks will have adequate representation on it for teachers and other academic persons.

9. The Board will function through a Standing Committee that will be assisted by panels of experts in various subjects fields.

10. The NCERT will provide the necessary academic services to the Board, both in bringing up problems for discussion as well as in helping the national and State level organisations engaged in the scrutiny, approval and production of textbooks to implement the decisions taken.

11. The Board shall meet as often as necessary but not less than once a year.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and Administrations of Union Territories and to all Ministries of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

G. K. CHANDIRAMANI, Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 24th December 1968

No. 24/3/68-FP.—In pursuance of the Resolution of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 1/29/58-FP dated the 5th February, 1959, as amended from time to time, the Central Government has nominated Shri M. V. Desai, acting Chairman, Central Board of Film Censors, as the Chairman of the Film Advisory Board, Bombay, in addition to his own duties, with immediate effect *vice* Shri R. P. Naik, till further orders.

BANU RAM AGGARWAL, Under Secy.